अरब–इजरायल द्वन्द और भारत की दोहरी वैदेशिक नीति

रमेश कुमार
शोध छात्र, इतिहास
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय
मुजफ्फरपुर

सारांश

आज भी इजरायल अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी विरोध जारी है। इजरायली सेना उसे अपनी भरपूर शक्ति से दबा रही है। इजरायल का कहना है कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन इजरायल अधिकृत क्षेत्र के फिलिस्तीनियों को उसका रहा है। बहरहाल वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। इसका कोई राजनीतिक सर्वमान्य हल खोजना चाहिए।

मध्यपूर्व की ऐसी ही राजनीतिक उहापोह की स्थिति में 15 नवम्बर 1988 को बहरीन में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर आराफात ने इजरायल अधिकृत इलाके में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की घोषणा की। इस घोषणा में यह उल्लेखित था कि इजरायल अधिकृत पश्चिमी तट और गाजा पट्टी इस राष्ट्र में शामिल किए गये है। जिसकी राजधानी जेरूसलेम बनाई गई है। अराफात की इस घोषणा के पश्चात ट्युनिशिया, इराक, मलेशिया, अल्जिरिया, सउदी अरब, कुवैत और भारत ने इस नये फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान कर दी। फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद् ने इजरायल के स्वतंत्र अस्तित्व के अधिकार को मान्यता तो दे दी है, किन्तु बहुत से सारे प्रश्न अभी अनसुलझे छोड़ दिया गया है। जो फिलिस्तीन और इजरायल के बीच तो कंटक एवं रोड़ा अटका ही रहे है लेकिन इससे भी बढ़कर अरब–इजरायल के युद्ध को जीवित रखे हुए है जो कभी भी ज्वालामुखी की भांति भभक उठेगा और विश्वशांति को भंग कर सकता है। अमेरिका एक तरफ इजरायल का अपना समर्थन जारी रखे हुए है और फिलिस्तीन की समस्या के समाधान के लिए झूठा स्वांग भी रच रहा है। मध्यपूर्व में वह इस समस्या को बनाए हुए है।

शब्द–कुंजी : अरब–इजरायल द्वन्द, वैदेशिक नीति, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन, पश्चिम एशिया, भू–राजनीति

भूमिका

भारत भी अपनी विदेश नीति के उन्हीं पदचिन्हों का राहगीर है जिस पर पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी और मनमोहन सिंह तथा सोनिया जी चल रही है। वस्तुतः भारत का हित इजरायल को खुलकर समर्थन देने का कभी नहीं रहा। वह अगर खुलकर समर्थन देगा भी तो अरब राष्ट्रो

को ही देगा, क्योकि भारत तेल आयात पर अरब राष्ट्रों पर निर्भर है। लेकिन नरेन्द्र मोदी की भाजपा की सरकार जब से भारत में सत्ता में आई है, तब से पश्चिम एशिया की राजनीति में कुछ बदलाव के लक्षण दिखाई देने शुरू हो गये है और भारतीय परराष्ट्र नीति संबंधी सोच में परिवर्त्तन दिखलाई पड़ने लगे है। भारत अब इजरायल से भी संबंध अच्छा बनाने का पक्षधर है क्योकि भारत को इजरायली हथियार की आवश्यकता है और जब तक भारत का संबंध इजरायल से अच्छा नहीं होगा तब तक इजरायल से हथियार प्राप्त करना भारत के लिए एक कठिन सौदा होगा।

आज भी इजरायल अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी विरोध जारी है। इजरायली सेना उसे अपनी भरपूर शक्ति से दबा रही है। इजरायल का कहना है कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन इजरायल अधिकृत क्षेत्र के फिलिस्तीनियों को उसका रहा है। बहरहाल वहाँ की स्थिति बड़ी खराब है। इसका कोई राजनीतिक सर्वमान्य हल खोजना चाहिए।

मध्यपूर्व की ऐसी ही राजनीतिक उहापोह की स्थिति में 15 नवम्बर, 1988 को बहरीन में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर आराफात ने इजरायल अधिकृत इलाके में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की घोषणा की। इस घोषणा में यह उल्लेखित था कि इजरायल अधिकृत पश्चिमी तट और गाजा पट्टी इस राष्ट्र में शामिल किए गए है जिसकी राजधानी जेरूसलेम बनाई गई है। अराफात की इस घोषणा के पश्चात् ट्युनिशिया, इराक, मलेशिया अल्जिरिया, सऊदी अरब, कुवैत और भारत ने इस नये फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान कर दी। फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद् ने इजरायल के स्वतंत्र अस्तित्व के अधिकार को मान्यता तो दे दी है, किंतु बहुत से सारे प्रश्न अभी अनुसलझे छोड़ दिया गया है जो फिलिस्तीन और इजरायल के बीच तो कंटक एवं रोड़ा अटका ही रहे है लेकिन इससे भी बढ़कर अरब–इजरायल के युद्ध को जीवित रखे हुए है जो कभी भी ज्वालामुखी की भांति भभक उठेगा और विश्व–शांति को भंग कर सकता है। अमेरिका एक तरफ इजरायल का अपना समर्थन जारी रखे हुए है और फिलिस्तीन की समस्या के समाधान के लिए झूठा स्वांग भी रच रहा है। मध्यपूर्व में वह इस समस्या को बनाए हुए है।

अमेरिका का कहना है कि किसी भी तरह की इकतरफा कार्रवाई से फिलिस्तीनियों को एक राष्ट्र निर्माण की मांग को धक्का पहुँचेगा। ओबामा प्रशासन का कहना है कि फिलहाल जरूरत है कि दोनो पक्ष करीब आए और बात करे। हवाईट हाउस का कहना है कि हम ऐसी किसी भी कदम का समर्थन नहीं करते जिससे दोनों देशों के संबंधों की खाई चौड़ी हो। इसके अलावा अमेरिका कतई अपने सबसे करीबी और मित्र देश इजरायल को नाराज भी नहीं करना चाहेगा।

भारत फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के प्रस्ताव को समर्थन देता है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा है कि भारत पहले ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुका है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को उनके देश को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता के लिए समर्थन देने का भरोसा दिया है। उन्होंने अब्बास को पत्र लिखकर इस बात का यकीन दिलाया है। भारत पहले भी बिना शर्त फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है।

फिलिस्तीनियों का तर्क है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने के विचार की शुरूआत अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ही की है। पिछले साल 23 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ओबामा ने कहा था कि उन्हें आशा है कि जब वे अगले साल यहाँ आयेंगे तब तक सहमति पत्र तैयार हो चुका होगा, जो एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र फिलिस्तीन के रूप में होगा और जो इजरायल संग शांति के साथ रह रहा होगा। फिलीस्तीनियों ने अब ओबामा को उनका भाषण याद दिलाने का फैसला किया है।

मध्यपूर्व शांति प्रक्रिया को पुनः जाग्रत करने के ओबामा के प्रयासों की शुरूआत इजरायल के अस्थायी बस्तियों का निर्माण रोकने से इनकार के साथ हो चुकी है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी फिलिस्तीन क्षेत्र में यहुदी बस्तियों के निर्माण को रोकने के बदले इजरायल को 3 अरब डॉलर के रक्षा सौदे का ऑफर देने का इच्छुक है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने अपने भाषण के नौ माह बाद शांति वार्ता में गति लाने के लिए अगला प्रयास किया। गत मई में उन्होंने कहा कि इजरायल और फिलिस्तीन की सीमा 1967 की सीमा के आधार पर आपसी सहमति से अदला–बदली के साथ तय की जानी चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमा का निर्धारण हो सके। एक बार फिर, फिलीस्तीनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के इस फर्मूले को मान लिया, पर नेतन्याहू ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। इससे फिलिस्तीनियों के पास 1967 की सीमा के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाने के अलावा कोई दूसरा अहिंसक रास्ता नहीं बच गया। उल्लेखनीय है कि जुन 1967 में हुए युद्ध में इजरायल ने ऐतिहासिक फिलिस्तीन के अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने संकल्प 242 की प्रस्तावना में कहा था कि बल के द्वारा भूमि पर कब्जा अस्वीकार्य है।

पहली बार नहीं है कि जब मध्य–पूर्व के संघर्ष में मध्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र का आह्वान किया गया है और न ही इसके लिए केवल फिलिस्तीनियों ने प्रयास किया है। इससे पहले 1947 में ब्रिटेन के कब्जे वाले फिलिस्तीन को यहूदी राष्ट्र और अरब राष्ट्र में बाँटने के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मतदान किया था, तब ब्रिटेन के कब्जे वाले फिलीस्तीन के यहूदियों ने तेल अवीव की सड़को पर जश्न मनाया था। आज इजरायली मूल विभाजन में अरबों को सौपें हिस्से के छोटे क्षेत्र में फिलीस्तीनी राज्यत्व की मान्यता को खारिज कर रहे है।

हालिया इतिहास पर गौर करें तो 1991 के मैड्रिट कॉन्फ्रेस के बाद से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच सीधी वार्ता कई रूपों में हो चुकी है। फिलिस्तीनियों ने एक के बाद एक कई समझौते मान लिए। इस उम्मीद के साथ कि ये आंशिक समझौते उनके राज्यत्व की राह प्रशस्त करेंगे। 1993 के ओस्लों समझौते ने शांति प्रक्रिया को गति प्रदान की, जिसके आधार पर पांच वर्षो में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के निर्माण और एक सुरक्षित और मान्यता प्राप्त इजरायल के साथ इस विवाद के अंत की आस लगायी गयी थी। लेकिन यह शांति प्रक्रिया धरातल पर किसी कारगर समझौते की नींव रखने में नाकाम साबित हुई। दुर्भाग्य से वार्ता न केवल नतीजा देने में नाकाम रही, बल्कि इसकी आड़ में फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल ने बड़े पैमाने पर यहूदी बस्तियों का निर्माण भी कर लिया। फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जे जारी है। वहाँ यहूदी बस्तियों का निर्माण भी जारी है और इजरायल की कथित 'सुरक्षा दीवार' ने फिलिस्तीनियों को सामाजिक और अर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साफ कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में निर्मित दीवार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिहाज से गैरकानूनी है। पर फैसले को लागू कराने की दिशा में अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है।

फिलिस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (P.L.O) के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने अब निरर्थक सीधी वार्ता की पहेली में उलझने की जगह संयुक्त राष्ट्र से मान्यता पाने का रास्ता चुना है। साफ है कि उनकी रणनीति में आये इस परिवर्त्तन ने न केवल इजराइलियों की कमजोर नस पर चोट किया है, बल्कि अमेरिका को भी निराश कर दिया है। केवल कुछ फिलिस्तीनियों को इस कदम में खामियाँ दिखती है, पर इससे तत्काल कोई ठोस नतीजा निकलने को लेकर संशय ज्यादातर के मन में है। फिलिस्तीनी जनता इस बात से खुश है कि उसे ऐसा नेतृत्व मिला है जो इजराइली और अमेरिकी दबाव के आगे मजबूती से खड़ा है। यह स्थिति फिलहाल अब्बास के लिए मददगार साबित होगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से उचित अवधि में कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिलने पर जनता वर्त्तमान राजनीतिक नेतृत्व और इजराइली कब्जेधारियों के खिलाफ भी हो सकती है।

ऐसे में अब्बास क्या पाने की उम्मीद कर रहे है? सुरक्षा परिषद् के विपरित जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा नहीं कर सकती और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को मान्यता देने के सुरक्षा परिषद् के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने वीटों पावर के इस्तेमाल की कसम खायी है। लेकिन यदि दो तिहाई, सदस्य राजी हो जाये, तो महासभा फिलिस्तीन को भी पर्यवेक्षक के दरजे के साथ राष्ट्र की मान्यता दे सकती हैं। जैसा कि वेटिकन को प्राप्त है। इसके अलावा, राष्ट्र (यहाँ तक कि पर्यवेक्षक का दरजा भी) के रूप में फिलिस्तीनी अंतर्राष्ट्रीय अदालत से कानूनी राहत की उम्मीद कर सकते है। संयुक्त राष्ट्र का समर्थन पाने की फिलिस्तीनियों की आकांक्षा का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वे अब इजराइल के साथ सीधी वार्ता बंद कर देगें। फिलिस्तीन के लोग अपने कब्जेधारियों से वार्ता नहीं कर रहे होंगे। बल्कि दो राष्ट्र अपने रिश्तों में शांति और सौहार्द कायम करने की कोशिश कर रहे होंगे।

भारत और फिलिस्तीन के बीच एतिहासिक संबंध है। दोनो देशों के बीच 1974 में यह कायम हुआ। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर दर्जा दिया। इस तरह भारत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (P.L.O) को मान्यता देने वाला पहला गैर–अरब देश बना। 1975 में भारत में फिलिस्तीन का दफ्तर खुला। मार्च 1980 से पूरी तरह राजनीतिक संबंध कायम हुए। वहीं भारत ने 25 जून 1996 को गाजा में अपना प्रतिनिधि दफ्तर खोला। इजरायल के साथ फिलिस्तीन के तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के वाजिब और कानूनी अधिकारों का समर्थन किया है। 2007 में अन्नपोलिस कांफ्रेन्स के दौरान भी भारत ने एक संप्रभु, स्वतंत्र और संयुक्त फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया। तत्कालीन विदेशमंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि फिलिस्तीन के भारत का यह समर्थन बिना किसी शर्त्त के है। अभी तक दोनों देशों के राष्ट्रध्यक्ष भी कई बार एक–दूसरे की यात्रा कर चुके है।

दूसरी ओर भारत ने यद्यपि कि फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान कर दिया है तथापि 1992 ई० में इजरायल को भी मान्यता प्रदान कर दिया है। आज की बदलती राजनीतिक परिवेश में भारत के लिए इजरायल की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। इजरायल के पास न्यूक्लीयर वीपेन है और फाइटर जहाज है। भारत को अपनी प्रतिरक्षा मजबूत करने के लिए उसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की यात्रा पर निकले है और उम्मीद है कि इजरायल से भारत को सामरिक एवं कूटनीतिक संबंध बढ़नेवाला है।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत इजरायल को खुलकर अपना समर्थन देने में हिचकिचा रहा था, वह स्थिति अभी नहीं है। भारत का सिरर्दद कश्मीर समस्या है और कश्मीर समस्या की प्रकृति करीब–करीब वही है जो इजरायल की है। इजरायल इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। फिलिस्तीनी

आतंकवादी इजरायल को चैन से रहने नहीं दे रहे है। इन फिलिस्तीनी आतंकवादियों को इस्लामिक यानी अरब मुस्लिम देशों का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है। ठीक यही स्थिति भारत की है। भारत में अलगाववादी या यों कहें कि कश्मीरी आतंकवादी भारत के विरूद्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को हर तरह की सहायता देकर भारत की बढ़ती हुई ताकत को कमजोर करने की हर कोशिश कर रहे है। उधर पाकिस्तान भी कश्मीरी आतंकवाद के नाम पर भारत को अस्थिर करने की हर कोशिश कर रहा है। अमेरिका को जिस तरह इजरायल का खुला समर्थन मिलता है, उस प्रकार का समर्थन भारत को नहीं मिलता है। अतः भारत परेशान है।

अक्षरधाम का धमाका हो या 1998 का बम्बई धमाका, संसद भवन का धमाका हो या वरलका का बम्बई धमाका, पंजाब में 2015–16 में दो–दो धमाके हुए सब धमाके पाकिस्तान की धरती से आइ एस आई एस तथा सेना के इशारे पर हो रहे है। ऐसी परिस्थिति में भारत अपनी सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए इजरायल से समर्थन लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इजरायल अरब आतंकवादियों के खिलाफ प्रशिक्षित सेना तथा गुरिल्ला युद्ध को आधार बनाकर युद्ध करता है।

जर्मन पत्रकार ने बताया कि आइ एस आइ एस के आतंकवादी अमेरिका तथा रूस की सैन्य शक्तियों से जितना नहीं डरते है उससे अधिक उनको इजरायल की सैन्य शक्ति से डर लगता है।

भारत की अपनी चिताएँ अपनी सुरक्षा को लेकर है। इजरायल ने कई बार भारत को यह संकेत दिया है कि अगर भारत चाहे तो इजरायल सैन्य सहायता भारत को देगा। यही तक नहीं उसने तो यह विश्वास भी दिलाया है कि भारत को सैन्यशक्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सैन्य प्रशिक्षण भी देने को तैयार है। अब गेंद भारत के पल्ले में है कि वह इजरायल के साथ सैन्य संबंध स्थापित करना चाहता है या नहीं। इसी को ध्यान में रखकर भारत की मोदी सरकार इजरायल की यात्रा पर जाने का निर्णय कर चुकी है। नरेन्द्र मोदी इजरायल की यात्रा करने वाले है और उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारत इजरायल ने फाइटर जेट खरीद सौदा करेगा और प्रतिरक्षा शक्ति आधुनिक बनायेगा।

उधर अमेरिका भी धीरे–धीरे इस स्थिति में आ रहा है जहाँ वह पाकिस्तान की आतंकवादी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा दिया है। अमेरिका के समक्ष पाकिस्तान से उतनी समस्या नहीं है जितनी रूस से है। अफगानिस्तान में रूस को हटाकर अमेरिका उस शून्यता को स्वयं अपने हित में भरना चाह रहा है। इसी बिंदु का फायदा उठाकर पाकिस्तान अमेरिका को ब्लैकमेल करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन इसकी कीमत अमेरिका को तो उठाना ही पड़ेगा, भारत को तो रोज ब रोज उठाना पड़ रहा है। अतः अमेरिका पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में बदलाव की स्थिति में पहुँच गया

है और अगर अमेरिका का झुकाव भारत के प्रति हुआ तो इससे इजरायल को भी बल मिलेगा क्योंकि इस्लामिक ताकतों को पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लीयर हथियार देकर इजरायल को घेर सकता है, जो अमेरिका को भी नागवार गुजरेगा। एक बात और अगर इजरायल के विरुद्ध खुल्लम–खुला पाकिस्तान अरब देशों को एटामिक मदद देने लगेगा तो इजरायल पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखकर भी अमेरिका पाकिस्तान को सामरिक एवं आर्थिक मदद दे रहा है। लेकिन एक दिन अमेरिका यह अनुभव करेगा कि उसकी यह सोच थोथी दलील ही निकलेगी। दूसरी ओर इजरायल भारत की ओर बहुत दिनों से झुक रहा है और अगर भारत भी इजरायल से मित्रता कायम कर लेता है तो पाकिस्तान की हेकड़ी बंद हो जायगी।

अतः अरब–इजरायल युद्ध में अमेरिका तथा भारत की चिंताएँ अपनी–अपनी हितों को लेकर जायज है और दोनों देश इस स्थिति से ऊपर उठने का प्रयास जल्द ही शुरू कर देंगे–ऐसी संभावना निकट भविष्य में दिखलाई पड़ रही है।

संदर्भ सूची

1. बी० एल० फाड़िया, *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति*, साहित्य सदन, आगरा, 1994, पृ० 425
2. गाँधीजी राय, *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति*, भारती भवन, पटना 2010, पृ० 330
3. पालमर एण्ड परकिन्स, *इन्टरनेशनल रिलेशन्स*, फोर्थ एडिशन, 2013, पृ० 348
4. बी० एल० फाड़िया, *अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पूर्वोक्त*, 2004, पृ० 528
5. *नवभारत टाइम्स*, अरब–इजरायल युद्ध और अमेरिका, न्यू देलही, 2012, पृ० 11–12
6. *टाइम्स ऑफ इंडिया*, न्यू दिल्ली, पृ० 16
7. *आउटलुक*, दिल्ली, 2015, दिसम्बर, पृ० 33–34
8. *इंडिया टूडे*, 2015, पृ० 16
9. *दैनिक भास्कर*, पटना, दिसम्बर, 19, 2015, पृ० 12